RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 17 JULY TO 23 JULY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 43 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

इस ऑयल कंपनी ने डिबेंचर के जरिये जुटाए 2,500 करोड़ रुपये, शेयरों ने एक साल में डबल किया पैसा Page 2

16.45 लाख नौकरियां खा गई नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की 'तिकड़ी', किन राज्यों पर पड़ी सबसे बड़ी मार Page 3

Jio, Airtel, Vi बायकॉट का कितना असर? बढ़े मोबाइल रिचार्ज के बाद की पहली TRAI रिपोर्ट Page 7

editorial

नीति आयोग का महत्व

केंद्र और राज्य सरकारों को समावेशी विकास के लिए रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह मुहैया कर नीति आयोग ने एक प्रमुख संस्था के रूप में अपने को स्थापित किया है. वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जब इसका गठन हुआ था, तब यह स्वाभाविक प्रश्न सामने था कि क्या यह अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पायेगा. आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 केंद्रीय मंत्रियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संस्था में शामिल किया है. अर्थशास्त्री सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष बने रहेंगे. पुनर्गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नयी सरकार में मंत्रियों का फेर-बदल हुआ है. वैज्ञानिक वीके सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, शिशु रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी संस्था के पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे. उल्लेखनीय है कि पूर्ण सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों के शीर्षस्थ पैनल के अलावा कई विशेषज्ञ, शोधार्थी और विद्वान विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करते रहते हैं.केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों के विद्वान, उद्योगपतियों आदि की शिरकत अलग-अलग बैठकों में समय-समय पर होती रहती है. योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग की कार्यशैली अधिक लचीली और समावेशी है. आयोग सरकारों को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, पर्यावरण आदि विभिन्न विषयों पर नीतियां बनाने में सलाह मुहैया कराता है. इसके प्रमुख कार्यों में सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन भी है. विकास से संबंधित विषयों पर शोध एवं विश्लेषण के कार्य के साथ-साथ सरकारों को आयोग उनकी क्षमता बढ़ाने में योगदान देता है. हालांकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और कई मंत्री आमंत्रित सदस्य हैं, पर इसकी कार्यशैली स्वायत्त है. अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल हेल्थ स्टैक जैसे कार्यक्रमों में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है. आयोग ने अनेक वार्षिक सूचकांक तथा रिपोर्ट भी प्रकाशित किये हैं, जो विकास के आयामों को समझने में बहुत मददगार हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पोषण, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आदि कई पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है. इन विषयों पर नीति आयोग सरकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. आयोग ने एक दशक से भी कम समय में प्रभावशाली सलाहकार के रूप में स्वयं को स्थापित किया है तथा राजनीतिक मतभेदों से भी मुक्त रहा है.

15 दिन और 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स...
क्यों बढ़नी चाहिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन?

नई दिल्ली। एजेंसी

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है। इस डेडलाइन में अब कुछ ही समय रह गया है। सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक 14 जुलाई तक 2.7 करोड़ टैक्सपेयर्स आईटीआर भर चुके हैं। पिछले साल आठ करोड़ से अधिक लोगों ने आईटीआर भरा था।

यानी अब भी पांच करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने आईटीआर नहीं भरा है। बहुत से टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर बहुत सारी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) ने इन मुद्दों को उठाया है और टैक्स डिपार्टमेंट से 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है।टैक्सपेयर्स को आईटी विभाग के पोर्टल में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें लॉग इन और पासवर्ड रीसेट जैसी मामूली दिक्कतें भी शामिल हैं। ITR फॉर्म में पहले से भरे गए डेटा में गड़बड़ी और ई-सत्यापन में कठिनाई जैसी बड़ी समस्याएं भी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार 14 जुलाई तक 2.7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13% ज्यादा है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का कहना है कि पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण डेडलाइन करीब आते-आते बड़ी संख्या में फाइलिंग प्रभावित हो सकती है।

क्या है दिक्कत

KSCAA की प्रेजिडेंट सुजाता जी ने कहा कि एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को समय पर आईटीआर भरने के लिए रिमाइंडर भेज रहा है, तो दूसरी तरफ पोर्टल पर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। IT रिटर्न फाइल करने में अब 15 दिन से भी कम समय बचा है। रिपोर्ट डाउनलोड करने में सुस्ती और पासवर्ड रीसेट करने के लिए OTP न आने जैसी दिक्कतों का सामना टैक्सपेयर्स को करना पड़ रहा है। KSCAA ने इस बारे में टैक्स डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखकर 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। यहां हम आपको उन समस्याओं के बारे में बता रहे हैं जिनका सामना टैक्सपेयर्स को करना पड़ रहा है...

1- इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करने में आ रही दिक्कत

टैक्सपेयर्स की शिकायत है कि वे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये व्यवधान सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड होने या मेंटनेंस गतिविधियों के कारण आ रहे हैं। इस कारण सर्विस में व्यवधान पैदा हो रहा है। इसी कारण पोर्टल पर दूसरी चीजें भी प्रभावित हो रही हैं।

2- AIS/TIS और फॉर्म 26AS डाउनलोड करने में समस्या

टैक्सपेयर्स इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें पोर्टल पर अहम दस्तावेजों को एक्सेस या डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या के कारण समय की काफी बर्बादी हुई है। आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा केवल 15 दिन दूर है। इससे टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ गई है। समय पर फाइल न करने के गंभीर परिणाम होते हैं। उन्हें जुर्माना और ब्याज शुल्क देना पड़ सकता है।

3- पहले से भरे गए डेटा में गड़बड़ी

कई मामलों में इनकम टैक्स पोर्टल पर पहले से भरे गए डेटा और फॉर्म 26AS/AIS में उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर दिखाई दे रहा है। इससे टैक्सपेयर्स में भ्रम और घबराहट का माहौल है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने और टैक्सपेयर्स के सामने आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता है।

4- AIS और TIS

इनकम टैक्स पोर्टल के AIS और TIS सेक्शन में डेटा पर रिस्पॉन्स सबमिट करने में समस्याएं आ रही हैं। टैक्सपेयर्स को इसे पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, जब रेस्पॉन्स सबमिट किए जाते हैं तो AIS या TIS में अपडेट करने में देरी होती है। इससे दिए गए डेटा की सटीकता और समयबद्धता प्रभावित हो रही है। इससे रिटर्न फाइल करने में देरी हो रही है।

5- पासवर्ड रीसेट करने में कठिनाई

OTP जेनरेट न होने के कारण टैक्सपेयर्स को अपना पासवर्ड रीसेट करने में कठिनाई हो रही है। यह समस्या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी कर रही है।

6- कर के भुगतान के लिए चालान बनाने में कठिनाई

पोर्टल पर कर भुगतान के लिए चालान बनाने में भी समस्या आ रही है। इससे टैक्सपेयर समय पर टैक्स और आईटीआर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इससे टैक्सपेयर्स समय पर टैक्स दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या का तुरंत समाधान करने की जरूरत है।

7- पॉप अप मेसेज में गलती

रिटर्न दाखिल करने के सबमिशन चरण के दौरान, अज्ञात और अस्पष्ट त्रुटि संदेश बार-बार दिखाई दे रहे हैं। इन त्रुटियों में अक्सर स्पष्ट समाधान या स्पष्टीकरण का अभाव होता है। इससे टैक्सपेयर को अपना आयकर रिटर्न समय पर पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

8- आय का रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई

इनकम टैक्स पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों और बफरिंग मुद्दों के कारण टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

9- आय के रिटर्न का ई-सत्यापन करने में कठिनाई

OTP प्राप्त न होने के कारण टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न ई-सत्यापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, ई-सत्यापन की समय सीमा को घटाकर 30 दिन करने से स्टेकहोल्डर्स के बीच चिंता बढ़ रही है।

10- एक से अधिक ध्ऊइ का जेनरेट होना

वास्तविक समय में OTP जेनरेट नहीं होने के कारण टैक्सपेयर्स कई OTP जेनरेट कर रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी भी OTP को मान्य नहीं किया जा रहा है। इससे विभिन्न फॉर्म और आयकर रिटर्न दाखिल करने में लोगों की हताशा और निराशा बढ़ रही है।

11- ITR रसीद डाउनलोड करने में कठिनाई

कई मामलों में स्टेकहोल्डर्स अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद ITR रसीद डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं।

इस ऑयल कंपनी ने डिबेंचर के जरिये जुटाए 2,500 करोड़ रुपये, शेयरों ने एक साल में डबल किया पैसा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की ऑयल सेक्टर की कंपनियों में इन दिनों शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। Nifty Oil and Gas सेक्टर ने इस साल में अब तक यानी ईयर टु डेट 37.85% का रिटर्न दिया है। इस बीच इएळ सेक्टर की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने कल एक्सचेंजों को जानकारी दी कि कंपनी ने डिबेंचर के जरिये 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

इस ऑयल रिफाइनरी कंपनी के पिछले कारोबारी दिन के शेयरों की प्राइस (IOC Share Price) देखा जाए तो इसके शेयर NSE पर 0.59% फीसदी की बढ़त के साथ सपाट पर बंद हुए। कंपनी के शेयर 1 अंक की बढ़त के साथ 170.70 रुपये पर बंद हुए थे। जबकि ओवरऑल, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो Nifty Oil and Gas में पिछले कारोबारी दिन 21.15 अंकों के साथ 0.16 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी।

आज IOCL के शेयरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोहर्रम के कारण शेयर बाजार बंद है। मगर एक साल का डेटा देखा जाए तो IOCL के शेयरों ने 97 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी अगर निवेशकों ने 1 लाख रुपये का निवेश छ्व्ण्ट के शेयरों में किया होगा तो उन्हें 97 फीसदी का मुनाफा मिला होगा। वहीं, 6 महीने में IOCL के शेयरों ने 28 फीसदी और 1 महीने में करीब 5 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कंपनी के शेयरों पर निवेशकों का क्या रिस्पांस रहेगा, इसके लिए अभी कुछ दिन का और इंतजार

करना पड़ सकता है। क्योंकि छ्व्ण्ट 30 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही का परिणाम (IOCL Q1 Results 2025) जारी करेगी। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निवेशकों के लिए काफी मायने रखती है।

डिबेंचर के जरिये जुटाए 2,500 करोड़ रुपये

IOCL ने शेयर बाजार को बताया कि इश्यू के माध्यम से जुटाए गए फंड का उपयोग मौजूदा उधार की रीफाइनेंशिंग और/या कंपनी के पूंजीगत खर्च (Capex) की फंडिंग के लिए किया जाएगा, जिसमें पहले से किए गए खर्च की भरपाई और/या बिजनेस के अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

IOCL ने शेयर बाजार को बताया कि उसने 16 जुलाई 2024 को प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर 2,500 करोड़ रुपये मूल्य के 2.5 लाख अनसिक्योर्ड, लिस्टेड, रेटेड, टैक्सेबल, रिडीमेबल, नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर जारी किए हैं।

मिलीं दो बोलियां

इकनॉमिक टाइम्स (ET) ने कल यानी 16 जुलाई को सूत्रों का हवाले से बताया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) को हरियाणा के पानीपत में कंपनी की रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने के लिए केवल दो बोलियां मिली हैं। प्रोजेक्ट के लिए दूसरे टेंडर के लिए बोलियां लगाई गईं। पहले वाले को प्रेफेंसियल ट्रीटमेंट के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था।

बोलीदाताओं में से एक GH4India है, जो ग्रीन हाइड्रोजन, इसके डेरिवेटिव और संबंधित रिन्यूबल एसेट्स को डेवलप करने के लिए IOC, ReNew और इंजीनियरिंग दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो (L&T) का एक जॉइंट वेंचर है।

मौजूदा सरकार का मिल रहा सपोर्ट

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यानी 17 जुलाई को भारत के एनर्जी सेक्टर की विदेशी संपत्तियों (overseas assets) की समीक्षा की, जिसमें भारतीय इएळ की विदेशी शाखाएं शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से ONGC विदेश लिमिटेड (OVL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड (BPRL), गेल इंडिया (GAIL India) और प्राइज पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PPCL) शामिल हैं।

पुरी ने कहा कि प्रदर्शन का आकलन करके और नए अवसरों की खोज करके, हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।'

ओमान के तट पर डूबे, अभियान शुरू

13 भारतीयों समेत 16 लोगों की तलाशी के लिए तैनात हुआ इंडियन नेवी का INS-Teg

ओमान। एजेंसी

ओमान की खाड़ी में डूबे 13 भारतीयों समेत 16 लोगों की तलाश के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग की तैनाती कर दी गई है। आईएनएस तेग को समुद्री निगरानी विमान पी-8आई के साथ ओमानी जहाजों और कर्मियों के साथ तैनात किया गया है। कोमोरोस-ध्वज वाले जहाज के डूबने के बाद खोज और बचाव अभियान चलाया जा सके। भारतीय युद्धपोत उस क्षेत्र में ऑपरेशनल टर्नअराउंड कर रहा था, जहां से उसे 15 जुलाई को खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि युद्धपोत ने 16 जुलाई की सुबह पलटे हुए तेल टैंकर का पता लगा लिया था।

समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार ओमान में 13 भारतीयों सहित 16 क्रू सदस्यों वाला एक कोमोरोस-ध्वजांकित तेल टैंकर समुद्र में पलट गया। टैंकर कथित तौर पर अदन के यमनी बंदरगाह की ओर जा रहा था और ओमान के प्रमुख औद्योगिक बंदरगाह डुक्म के पास पलट गया। इसमें सभी 16 लोग अब तक लापता हैं। खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग को समुद्री निगरानी विमान पी-8आई के साथ ओमान के तट पर तैनात किया गया है। लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश में भारतीय युद्धपोत और विमानों को ओमानी जहाजों और कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

डूबने वालों में 3 श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल

समुद्री सुरक्षा केंद्र ने मंगलवार को पुष्टि की कि ओमान के प्रमुख औद्योगिक बंदरगाह डुक्म के पास कोमोरोस-ध्वजांकित तेल टैंकर, जिसमें 13 भारतीयों सहित 16 चालक दल थे। ओमानी सेंटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'प्रेस्टीज फाल्कन' के चालक दल में 13 भारतीय नागरिक और तीन श्रीलंकाई शामिल थे। अफ्रीकी देश कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर ओमान के तट पर डूबने के बाद लापता हो गया, जिससे उसमें सवार चालक दल के 16 सदस्य लापता हो गए। जहाजरानी वेबसाइट 'मरीन ट्रैफिक डॉट कॉम' के अनुसार, यह जहाज दुबई के हमरिया बंदरगाहर से रवाना हुआ था और यमन के बंदरगाह शहर अदन की ओर जा रहा था। दुक्म बंदरगाह ओमान की प्रमुख तेल और गैस खनन परियोजनाओं का मुख्य हब है।

डिफेंस, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आने वाली है गुड न्यूज, FDI के लिमिट की समीक्षा करेगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गुड न्यूज है। इन सेक्टर्स के लिए बजट में अहम घोषणा हो सकती है। सरकार डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लांटेशन जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा की समीक्षा करने पर विचार कर रही है। साथ ही इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं पर विचार कर रही है। अधिकांश क्षेत्रों में उदार व्यवस्था है जहां ऑटोमैटिक अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) इस बात पर विचार कर रहा है कि डिफेंस के लिए निवेश मानदंडों को कैसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि सरकार रणनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करना चाहती है।मौजूदा नियम इस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति देते हैं, जहां भी किसी यूनिट की एंट्री से आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्राप्त होती है। स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक एफडीआई की अनुमति है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। इनमें कुछ क्षेत्रों और छोटे हथियारों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग शामिल है। इसके अंतर्गत कुछ शर्तें भी हैं, जिनकी समीक्षा की जा सकती है। बीमा क्षेत्र को 25 साल पहले विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था। सामान्य या जीवन बीमा कंपनी में एफडीआई की सीमा 74% है, जबकि बीमा मध्यस्थों में 100% एफडीआई की अनुमति है।

डॉलर, पाउंड, यूरो नहीं, यह है दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी

अमेरिकी मुद्रा टॉप 5 में भी नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

फॉरेन करेंसी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले डॉलर, पाउंड और यूरो का जिक्र होता है। डॉलर, पाउंड और यूरो भले ही लोकप्रिय मुद्राएं हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी नहीं हैं। सच तो यह है कि कुवैती दिनार (KWD) दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। 1 कुवैती दिनार की कीमत करीब 271 भारतीय रुपये के बराबर है। कुवैती दिनार इतना मूल्यवान क्यों है, इसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है कि इसका तेल निर्यातक होना। कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है। चूंकि तेल ग्लोबल कमोडिटी है और इसकी मांग अक्सर अधिक रहती है। ऐसे में कुवैती दिनार की मांग भी बढ़ जाती है। इसके चलते दिनार का मूल्य बढ़ जाता है।

दिलचस्प यह है कि जिस डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया मानती है, वह टॉप 5 मूल्यवान में भी शामिल नहीं है। कुवैती दिनार के बाद बहरीन दिनार (BHD) का नंबर आता है। एक बहरीन दिनार का मूल्य करीब 221 भारतीय रुपये के बराबर है। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी में बहरीन के बाद तीसरे नंबर पर ओमानी रियाल (OMR) है। चौथे पर जॉर्डीनियन दिनार (JOD) और पांचवें पर जिब्राल्टर पाउंड (GIP) है। यानी डॉलर टॉप 5 में भी नहीं है।

क्यों इतना मूल्यवान है दिनार?

कुवैती दिनार के इतना मूल्यवान होने के पीछे कई कारण हैं। इनमें तेल निर्यात, राजनीतिक स्थिरता और कुवैत का छोटी अर्थव्यवस्था होना शामिल है। दरअसल, कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शुमार है। तेल एक वैश्विक वस्तु है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मांग बनी रहती है। इस तरह कुवैती दिनार की मांग भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि इसका मूल्य बढ़ जाता है। इसके अलावा कुवैत अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से स्थिर देश रहा है। यह निवेशकों को आकर्षित करता है और मुद्रा को मजबूत करता है। तीसरी वजह यह है कि कुवैत अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि मुद्रा की आपूर्ति सीमित है। सीमित आपूर्ति ऊंची मांग के साथ मिलकर मुद्रा के मूल्य को बढ़ाती है।

कौन से फैक्टर करेंसी के मूल्य पर डालते हैं असर?

आर्थिक स्थितिः एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाली मुद्रा का मूल्य आमतौर पर अधिक होता है।

ब्याज दरें: ऊंची ब्याज दरें विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं, जिससे मुद्रा की मांग बढ़ती है और इसका मूल्य बढ़ जाता है।

महंगाई की दरः ऊंची मुद्रास्फीति वाली मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम होता जाता है।

राजनीतिक स्थिरताः राजनीतिक रूप से स्थिर देशों की मुद्राएं आमतौर पर अधिक मूल्यवान होती हैं।

वस्तुओं का व्यापारः जो देश विदेशी बाजारों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात करते हैं, उनकी मुद्राएं आमतौर पर मजबूत होती हैं।

16.45 लाख नौकरियां खा गई नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की 'तिकड़ी', किन राज्यों पर पड़ी सबसे बड़ी मार

नई दिल्ली। एजेंसी

नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी के कारण देश में इनफॉर्मल सेक्टर में सात साल में करीब 16.45 नौकरियां स्वाहा हो गईं। सरकारी आकड़ों में यह बात सामने आई है। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों की संख्या 16.45 लाख यानी करीब 1.5 फीसदी घटकर 10.96 करोड़ रह गई जो 2015-16 में 11.13 करोड़ थी। नोटबंदी की घोषणा नवंबर 2016 में की गई थी जबकि जीएसटी जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसी तरह कोरोना महामारी ने मार्च 2020 में देश में दस्तक दी थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2015-16 के बाद पहली बार यह आंकड़ा जारी किया है। मंत्रालय ने अनइनकॉरपोरेटेड एंटरप्राइजेज के 2021-22 और 2022-23 के आंकड़े जारी किए हैं।

Annual Survey of Unincorporated Enterprises (ASUSE) के मुताबिक अनइनकॉरपोरेटेड एंटरप्राइजेज की संख्या 2015-16 में 6.33 करोड़ थी जो 2022-23 में बढ़कर 6.50 करोड़ पहुंच गई। यानी इस संख्या में 16.56 लाख की बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की सबसे ज्यादा मार इनफॉर्मल सेक्टर को ही झेलनी पड़ी है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडीशा में 2015-16 और 2022-23 के बीच अनौपचारिक रोजगार में तेजी आई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या में गिरावट आई। देश में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले करीब दो-तिहाई कामगार इन्हीं 10 राज्यों में हैं।

राज्यों का हाल

सर्वे के मुताबिक देश के 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 16 में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या में 2022-23 में पिछले सर्वे के मुकाबले गिरावट आई है। पिछला सर्वे 2019 में आया था जिसमें 2015-16 के आंकड़े दिए गए थे। लेकिन इनसे यह बात भी सामने आई है कि महामारी के तुरंत बाद अधिकांश राज्यों में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या में तेजी आई थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या 2015-16 में 1.65 करोड़ थी लेकिन 2022-23 में यह 1.57 करोड़ रह गई। 2021-22 में राज्य में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या 1.30 करोड़ थी। पश्चिम बंगाल में भी यह स्थिति रही।

इस बीच महाराष्ट्र में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या में 2015-16 में 91.23 लाख थी जो 2022-23 में 1.15 करोड़ पहुंच गई। इस दौरान मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में भी इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या में तेजी आई। देश में प्रवासी मजदूरों के सबसे बड़े स्रोत बिहार में साल 2015-16 और 2021-22 के बीच इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या में गिरावट आई लेकिन 2022-23 में इसमें भारी देखने को मिली और यह संख्या महामारी से पहले के दौर से भी ऊपर पहुंच गई। राज्य में 2015-16 में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की संख्या 53.07 लाख थी जो 2021-22 में 43.22 लाख रह गई। लेकिन 2022-23 में यह बढ़कर 58.95 लाख पहुंच गई।

Credit Card से की गई खरीदारी पर मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानें क्या कहता है नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना महामारी के बाद से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले मेट्रो सिटी से लेकर छोटे शहरों में लगातार बढ़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल युवा काफी कर रहे हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि Credit Card से बड़े ट्रांजैक्शन यानी बड़ी खरीदारी जांच के दायरे में आता है। इनकम टैक्स विभाग क्रेडिट कार्ड से होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन पर नरज रखता है। अगर उसे कुछ शक होता है तो वह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजकर जवाब मांगता है।

क्रेडिट कार्ड से उच्च-मूल्य लेनदेन क्या है?

उच्च-मूल्य लेनदेन उन वित्तीय लेन-देन को कहते हैं जो विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित एक निश्चित सीमा का उल्लंघन करते हैं। आयकर विभाग इन लेन-देन पर कड़ी नजर रखता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के लिए इनका इस्तेमाल होने की संभावना होती है। रिजर्व बैंक भी ऐसे लेन-देन को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों के पालन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है।

क्रेडिट कार्ड से अधिकतम कितनी राशि खर्च कर सकते हैं?

क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं हैं, लेकिन बैंकों को आयकर विभाग को उच्च मूल्य के लेन-देन की रिपोर्ट करना आवश्यक है। वित्तीय संस्थानों को फॉर्म 61A का उपयोग करके 10 लाख रुपये से अधिक के किसी भी लेन-देन की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसलिए कोशिश करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी न करें। साथ ही बहुत बड़ी खरीदारीया ट्रांजैक्शन से बचें। अगर ऐसा करेंगे तो परेशानी से बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग को व्यक्तियों को फॉर्म 26AS में उच्च मूल्य के क्रेडिट कार्ड लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। याद रखें, आपको अपनी खर्च सीमा से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयकर विभाग सभी क्रेडिट कार्ड लेन-देन की निगरानी कर रहा है। आपके क्रेडिट कार्ड का विवरण आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, और आपके सभी खर्चों को सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैक किया जाता है। आयकर नियमों के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उच्च-मूल्य वाले लेन-देन की सूचना देनी चाहिए।

गेमिंग कंपनी को GST नोटिस, नहीं चुकाए हैं 1,120 करोड़ टैक्स

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स कंपनी Nazara Technologies की दो सहायक कंपनियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इन दोनों कंपनियों को गुड एंड सर्विस टैक्स डिपॉर्टमेंट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जीएसटी विभाग ने अपने नोटिस में 1,120 करोड़ रुपये के टैक्स देनदारी का जिक्र किया है. इस बात की जानकारी कंपनी ने बुधवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

मंगलवार को जारी किया गया नोटिस

Nazara Technologies ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक, कोलकाता ने ओपनप्ले टेक्नोलॉजीज और हालाप्ले टेक्नोलॉजीज को मंगलवार, 16 जुलाई को क्रमशः 845.72 करोड़ रुपये और 274.21 करोड़ रुपये की प्रस्तावित देनदारी के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है।

कपंनी ने दिया जवाब

कंपनी ने नोटिस के जवाब में कहा कि ये दावे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के विपरीत खिलाड़ियों द्वारा जुटाई गई राशि के आधार पर जीएसटी की कैलकुलेशन से संबंधित है। कंपनी ने आगे कहा, 'दोनोंसब्सिडियरी कंपनियां अपने लीगल एडवाइजर और टैक्स एडवाइजर्स के साथ नोटिस का रिव्यू कर रही हैं ताकि आगामी भविष्य कार्रवाई का सामना किया जा सके..' कपंनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में आगे जानकारी दी कि वित्त साल 2023-24 की आखिरी तिमाही में इन दोनों कंपनियों ने सामूहिक रूप से इसके रेवेन्यू में 2 प्रतिशत से कम और इसके प्रॉफिट में 1इ से कम का योगदान दिया। बता दें कि मंगलवार, 16 जुलाई को शेयर मार्केट में नाज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयर 923.20 रुपये पर क्लोज हुए थे।

बता दें कि बुधवार को मुहर्रम का सर्वाजनिक अवकाश के कारण भारतीय शेयर बाजार में भी छुट्टी है. बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई कामकाज नहीं हुआ है। हालांकि 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून को समाप्त हुई तिमाही के लिए कंपनियां अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हैं। गुरुवार को सुबह 9:30 बजे शेयर बाजार अपने निर्धारित समय से खुलेगा. ऐसे में जिन कंपनियों ने आज अपने रिजल्ट पेश किए हैं, उनके शेयरों पर नजर रहेगी।

बजट में रुपए 5 लाख होगी बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट! फोकस में नौकरीपेशा लोग

नई दिल्लीः वस्तुओं और सेवाओं पर आम लोगों की ओर से होने वाले खर्च में सुस्ती के बीच वित्त वर्ष 2025 के लिए पेश किए जाने वाले आम बजट में सरकार टैक्स के मोर्चे पर कुछ रियायतें दे सकती है। सरकार का जोर ओल्ड टैक्स रिजीम के बजाय अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम की ओर लाने पर है। लिहाजा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने जैसे कदम उठा सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे नई कर व्यवस्था का आकर्षण बढ़ेगा।वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की GDP ग्रोथ के साथ लगातार तीसरा साल रहा, जब इकॉनमी बढ़ने की रफ्तार 7% से अधिक रही। लेकिन, अर्थव्यवस्था का करीब 60% हिस्सा जिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE) पर टिका है, उसकी ग्रोथ 4% ही रही। विशेषज्ञ इसे बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए जाने पर जोर दे रहे हैं।

Banking Fraud:

RBI के नए नियम जान लीजिए, ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो फ्रॉड कहा जाएगा

नई दिल्ली। एजेंसी

इन दिनों बैंक खाते से जुड़े फ्रॉड की खबरें कुछ ज्यादा ही आ रही है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों सहित वाणिज्यिक बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर दिशानिर्देशों Master Directions on Fraud Risk Management पर संशोधित नियम जारी किए हैं। हम यहां बता रहे हैं कि इनमें क्या-क्या शामिल हैं।

क्या कहा है आरबीआई ने

आरबीआई ने 16 जुलाई, 2024 को जारी एक सर्कुलर में कहा, 'यह मास्टर डायरेक्शन पहले के मास्टर डायरेक्शन, सर्कुलर और उभरते मुद्दों की व्यापक समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह मास्टर दिशानिर्देश सिद्धांत-आधारित हैं और विनियमित संस्थाओं (आरई) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र प्रशासन और निरीक्षण में बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं।

तीन मास्टर डाइरेक्शन्स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं। पहला है वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, दूसरा है सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक) और तीसरा है नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित)। इन निर्देशों का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और ग्रामीण सहकारी बैंकों में बेहतर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचे और प्रणालियों को प्रोत्साहित करना है। नियामक के अनुसार, समायोजन के बाद, आरबीआई ने नियमों को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के प्रयास में इस विषय पर पिछले 36 परिपत्रों को हटा दिया है।

इनमें से श्रेणी का करना होगा चयन

जब बैंक धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न (एफएमआर) दाखिल करके वेब पोर्टल के माध्यम से आरबीआई को धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं तो एकरूपता और स्थिरता बनाए रखने के लिए, उन्हें नीचे दी गई सूची से सबसे प्रासंगिक श्रेणी का चयन करना होगा:

(i) धन का दुरुपयोग और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन;
(ii) जाली उपकरणों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण;
(iii) खातों की पुस्तकों में हेरफेर या फर्जी खातों के माध्यम से, और संपत्ति का रूपांतरण;
(iv) किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से तथ्यों को छिपाकर धोखाधड़ी करना और प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी करना;
(v) कोई गलत दस्तावेज/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाकर धोखाधड़ी करने के इरादे से जालसाजी;
(vi) धोखाधड़ी के इरादे से किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, मूल्यवान सुरक्षा या खाते का जानबूझकर मिथ्याकरण, विनाश, परिवर्तन, विकृति;
(vii) अवैध संतुष्टि के लिए धोखाधड़ीपूर्ण ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं
(viii) धोखाधड़ी के कारण नकदी की कमी;
(ix) विदेशी मुद्रा से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन;
(x) धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग/डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन।

वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में किया सफर तो नप जाएंगे, बदल गया नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रेलवे का इतिहास काफी पुराना है। भारत दुनिया के सबसे लंबे रेल नेटवर्क में से एक है। 177 साल पुराना भारतीय रेलवे 68,000 किलोमीटर से अधिक में फैला है। यात्रा करने के लिए ज्यादातर लोगों की पहली पसंद ट्रेन ही है। अबी भी लोग लंबी दूरी का सफर आमतौर पर ट्रेन के जरिए पूरा करते हैं। लोगों के सफर करने के लिए भारतीय रेलवे ने नियम भी बनाए हैं। जिसका पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। इसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ा है। दरअसल, रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर सफर को लेकर सख्त फैसला किया है। वेटिंग टिकट वाले अब रिजर्वेशन बोगी में सफर नहीं कर सकते हैं।

कहा जा रहा है कि अगर किसी यात्री ने अब नियम को तोड़ा तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऊर्ऊ उसे ट्रेन से भी उतार सकता है। इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं।

वेटिंग टिकट वाले स्लीपर और एसी बोगी में नहीं कर सकते सफर

अगर आपका टिकट वेटिंग में है तो रिजर्वेशन कोच में सफर नहीं कर सकते हैं। भले ही आपका टिकट विंडो से ही क्यों न लिया गया हो। ऑनलाइन टिकट तो वैसे ही वेटिंग टिकट होने पर कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह के टिकट पर भी अब रेलवे ने रिजर्वेशन बोगी में सफर करने पर रोक लगा दी है। वैसे तो यह फैसला रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट के साथ सफर करने वालों की सहूलियत के लिए लागू किया गया है। लेकिन इसका वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि यह नियम पहले से ही था। अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर आपका टिकट कैंसल करवाना ही बेहतर है।

यात्रियों की शिकायत पर सख्ती

दरअसल, कुछ महीनों पहले वेटिंग टिकट वालों की भीड़ रिजर्वेशन कोच में बढ़ गई थी। इससे कंफर्म टिकट वाले अपनी सीट तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में रेलवे से शिकायत की गई थी। इसके साधार पर रेलवे ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यात्रियों को असुविधाओं को लेकर 45 फीसदी शिकायतें रेलवे को मिली थी। ऐसे में स्लीपर और एसी कोच में रिजर्वेशन कोच में वेटिंग टिकट वालों को सफर पर रोक लगा दी गई है।

वेटिंग टिकट पर पकड़े गए तो क्या होगा

नए नियम के लागू होने के बाद अगर कोई यात्री स्लीपर कोच में विंडो वेटिंग टिकट के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बीच सफर में ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। इसके अलावा इस नए नियम के जरिए TTE को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह यात्री को बीच सफर में उतारने के बजाय उसे जनरल डिब्बे में भेज सकता है।

अब अस्पताल से छुट्टी मिलने में नहीं होगी देर, सरकार ने कर दिया इंतजाम, आप भी जानिए

नई दिल्ली। एजेंसी

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज देने वाली कम से कम 33 बड़ी कंपनियां नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (NHCX) से जुड़ गई हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सरकार ने बीमा दावों से जुड़ी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए बनाया है। अभी तक यह काम कई अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए होता था जिससे समय बहुत लगता था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि NHCX के इस्तेमाल से न सिर्फ बीमा दावों की प्रक्रिया तेज होगी बल्कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी भी बनेगी। इससे देश की शीर्ष बीमा नियामक संस्था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के पास दावों के निपटान की स्थिति की रीयल टाइम जानकारी होगी।नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आम लोग भी मोबाइल के जरिए अपने बीमा दावे की स्थिति देख सकेंगे। NHA ने ही इस सेंट्रल प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों ने परीक्षण के तौर पर NHCX के माध्यम से दावों का निपटान शुरू कर दिया है और जल्द ही सभी सुविधाओं के साथ प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की प्रमुख कंपनी HDFC Ergo ने NHCX के माध्यम से अपना पहला दावा निपटाया है। NHA ने IRDAI के सहयोग से NHCX को विकसित किया है।

डॉ. देवी शेट्टी ने किया है कमाल, एक करोड़ रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, महज 10 हजार रुपये के सालाना प्रीमियम में

क्या होगा बदलाव

सूत्रों ने कहा कि NHCX का उद्देश्य फिलहाल कारोबार को नियंत्रित करना नहीं है, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भविष्य में ऐसी प्रणालियां विकसित करने के लिए किया जा सकता है जिनको प्लेटफॉर्म में जोड़ा जा सके ताकि अनुचित आधारों पर दावों को अस्वीकार करने जैसी गड़बड़ियों को रोका जा सके। अभी इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले मरीज अपनी बीमा पॉलिसी का विवरण या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर या बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया कार्ड दिखाते हैं। इसके बाद अस्पताल संबंधित बीमा कंपनियों के क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल पर जाता है और पूर्व अनुमोदन या दावा अनुमोदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करता है।

पूर्व-अनुमोदन/दावा प्रपत्र प्राप्त होने पर, बीमा कंपनी/थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपने आंतरिक दावा प्रसंस्करण पोर्टल का उपयोग करके फॉर्म को प्रमाणित और डिजिटाइज करता है। फिर संबंधित टीम द्वारा दावों का फैसला किया जाता है। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि अक्सर, मरीजों को इस प्रक्रिया के पूरा होने के लिए दिन भर इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण अस्पताल से छुट्टी मिलने में देरी होती है और अतिरिक्त कमरे का किराया देना पड़ता है। ऊर्ऊ के साथ, वे अपने दावों के निपटान की प्रगति की निगरानी स्वयं कर सकेंगे। यह एक बड़ी राहत की बात है।

इंदौर की योग प्रशिक्षक डॉ. भारती दुबे ठाकुर को योग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि

इंदौर। एजेंसी

प्रख्यात योग प्रशिक्षक 46 वर्षीय इंदौर की डॉ. भारती दुबे ठाकुर को मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से योग विषय में डॉक्टोरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आज यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि डॉ. भारती दुबे ठाकुर जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं, को इनकी योग से जुड़ी विगत 15 वर्षों के अनुभवों एवं विशेषज्ञता के लिये यह सम्मान मिला है। बतादें कि डॉ. भारती दुबे ठाकुर ने कईयों को योग में प्रशिक्षित किया और मार्गदर्शन दिया है, विशेष रूप से महिलाओं को, जिन्हें डॉ. भारती दुबे ठाकुर के मार्गदर्शन में उनके स्वास्थ्य और जीवनशैली को सुधारने के लिए योग द्वारा मदद मिली। पिछले दशक में डॉ. भारती ठाकुर ने स्कूल और कार्यालयों में योग संबंधित वर्कशॉप कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जनता को योग के विविध लाभों के बारे में जागरूक किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया, दिनचर्या कार्यों और योग प्रथाओं के बीच संबंध को ज़ोर दिया। डॉ. भारती दुबे ठाकुर का यह मानना है कि महिलाओं को उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत को प्राथमिकता देना चाहिये और दिनचर्या में योग का अभ्यास नियमित करते रहना चाहिए। डॉ. भारती दुबे

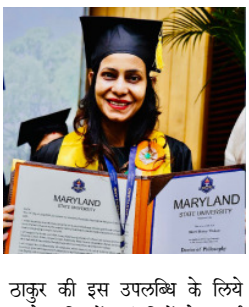

ठाकुर की इस उपलब्धि के लिये उनके परिजनों एवं मित्रों ने बधाई प्रेषित की है। बतादें कि मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा समारोह में डॉ. अशोक कुमार गड़िया अध्यक्ष, मेवाड़ समूह के संस्थान चांसलर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, डॉ. एस. अदिनारायण, पीएचडी डेप्यूटी प्रवर्तन अधिकारी (आर) प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत सरकार, नई दिल्ली और ज्यूरी, डॉक्टोरल मॉनिटरिंग बोर्ड मैरिलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, माननीय बसेम एफ. हेलिस काउंसलर फिलिस्तीन के दूतावास, डॉ. अबेद इलराजेग अबु जेजर फिलिस्तीन दूतावास मीडिया सलाहकार, डॉ. टांजैर वशिष्ठा लेडी ऑफ होनर मान्यवर प्रतिनिधि शांति एवं खेल परिषद, अफगानिस्तान (भारत में), श्री प्रदीप खत्री, एचपीएस हरियाणा के उप पुलिस अधीक्षक, डॉ. विक गैफनी निदेशक (एशिया / पेसिफिक) कवेती लॉ फर्म, ऑस्ट्रेलिया और सेनेटर, मैरिलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, एडवोकेट नवनीत मोमी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून विशेषज्ञ एलएलएम, मैंचेस्टर विश्वविद्यालय, इंग्लैंड, मिस्टर चार्ल्स थॉमसन सीनियर जर्नलिस्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया और सदस्य, डॉक्टोरल मॉनिटरिंग बोर्ड मैरिलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉ. परीन सोमानी निदेशक लंदन संगठन ऑफ स्किल डेवलपमेंट (एलओएसडी), यूके, मिस्टर्स ब्रांका वैन डेर लिंडेन लेखक, साइप्रस और सेनेटर, एमएसयू, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रोफ़ेसर डॉ. पी.के. राजपूत पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कैडिला और एशिया हेड, मैरिलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, मिस्ट्रेस सिम्मी हार्डिंग सीईओ ग्लोबल एजुकेशन बोर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य शिक्षा अधिकारी वाईजीय सिखानेवाला एकेडमी और सेनेट सदस्य, मैरिलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी (एमएसयू), डॉ. एवजेनिया झारिकोवा प्रोफ़ेसर और अंतरराष्ट्रीय एकेडेमीशियन ओडेसा, यूक्रेन और सदस्य, डॉक्टोरल मॉनिटरिंग बोर्ड एमएसयू, यूएसए, रिंगो गॉस्लर प्रमाणित नेतृत्व और टीम प्रशिक्षक, जर्मनी और यूएसए के संत, डॉ. नेल्ली फारदोनोवा प्रसिद्ध शिक्षाविद, रूस आदि अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

LIC Investment: अडानी, पतंजलि, HAL जानिए किन-किन कंपनियों के शेयर खरीद रही है एलआईसी

मुंबई। एजेंसी

सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी (Life Insurance Corporation of India) को तो जानते ही होंगे। यह सिर्फ बीमा का धंधा ही नहीं करती है। इस कंपनी का रियल एस्टेट समेत कई सेक्टर में एक्सपोजर है। यह शेयर बाजार में भी अच्छा-खासा निवेश करती है। कई आईपीओ को तो इसी ने सफल बनाया है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर है। हम आपको बता रहे हैं कि इस साल जून में समाप्त तिमाही Q1FY25 के दौरान कंपनी ने किन-किन कंपनियों में निवेश किया है।

पहली तिमाही में कहां हुआ है निवेश

LIC ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही या Q1FY25 के दौरान केमिकल्स, बैंक, सीमेंट और रक्षा सहित अन्य सेक्टर्स की चुनिंदा कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये वही कंपनियां हैं, जिनकी वजह से इस दौरान बेंचमार्क BSE सेंसेक्स में 7% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान ब्रॉडर बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमशः 17% और 21% की बढ़ोतरी हुई।

अडानी ग्रुप की कंपनियों में बढ़ा है निवेश

इनिशियल शेयरहोल्डिंग डेटा से पता चला है कि देश के सबसे बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक थ्ध्य ने तिमाही के दौरान अदानी समूह के कुछ शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसने इस साल अप्रैल से जून के दौरान अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 3.68% कर दी, जो मार्च 2024 की पिछली तिमाही में 3% थी। इसी तरह, इसने उसी तिमाही के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज में

अपनी हिस्सेदारी 3.93% से बढ़ाकर 4.07% कर दी।

इस कंपनी पर लगाया दांव

एलआईसी ने बीती तिमाही के दौरान सरकारी कंपनी भारत पर्यटन विकास निगम के साथ साथ एडोर वेल्डिंग, पूनावाला फिनकॉर्प और पीएसपी प्रोजेक्ट्स में 1% से अधिक हिस्सेदारी भी ले ली। बीएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछली तिमाही में एलआईसी इन कंपनियों के प्रमुख शेयरधारकों में से नहीं थी।

सीमेंट सेक्टर में बढ़ रही है हिस्सेदारी

इस बीमा कंपनी ने सीमेंट सेक्टर में भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। बीते जून में समाप्त तिमाही के दौरान एलआईसी ने श्री सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 3.91% से बढ़ाकर 4.19% कर दी। इसने अल्ट्राटेक सीमेंट (1.49% से 1.62% तक), और द रैमको सीमेंट्स (6.37% से 7.10% तक) में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। उल्लेखनीय है कि ब्रोकिंग फर्म केआरचोकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज KRChoksey Shares and Securities ने द रैमको सीमेंट्स पर 839 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'एक्यूमुलेट' रेटिंग दी है। दूसरी ओर, इसने 30,662 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ श्री सीमेंट पर 'खरीदने' की सलाह दी है।

एसबीआई में भी बढ़ी हिस्सेदारी

एसीई इक्विटी ACE Equity के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एलआईसी ने इसी अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अपनी हिस्सेदारी 8.93% से बढ़ाकर 9.06% कर दी है। इसने कोटक महिंद्रा बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी पहले के 6.46% से बढ़ाकर 6.99% कर दी। 1.28 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ, एलआईसी के पास अब अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज में 2.86% हिस्सेदारी है। बीती तिमाही के दौरान अपोलो टायर्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, एसजेवीएन, भारत डायनेमिक्स, दीपक नाइट्राइट, टाइटन कंपनी, पतंजलि फूड्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन अन्य कंपनियों में शामिल हैं जिनमें एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

LIC शेयर का क्या है भाव

एलआईसी के शेयर बीएसई में कल 1060 रुपये पर बंद हुए थे। आज यह 1065.05 रुपये पर खुला और शीघ्र ही 1089.90 रुपये पर चला गया। सुबह साढ़े नौ बजे यह 1083.65 रुपये पर ट्रेड हो रहा था।

SW मोटर इंडिया के सीईओ ने कहा, यात्री वाहनों पर मौजूदा जीएसटी दर में बदलाव की जरूरत

नई दिल्ली। एजेंसी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के मानद मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजीव छाबा ने कहा है कि भारत में यात्री वाहनों पर मौजूदा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दर संरचना काफी पुरानी हो चुकी है। इसे मोटर वाहन उद्योग में हो रहे नए घटनाक्रमों के अनुरूप बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को मोटर वाहन क्षेत्र पर नीतियां बनाते समय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, आयात बिल में कमी, सतत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और स्वामित्व की कुल लागत के समग्र परिप्रेक्ष्य पर विचार करना चाहिए।

केंद्रीय बजट से पहले हाइब्रिड वाहनों को कर प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार किए जाने की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि केवल मजबूत 'प्लग-इन' हाइब्रिड वाहन पर ही ऐसे लाभ के लिए विचार किया जाना चाहिए, जिनमें परंपरागत इंजन से स्वतंत्र बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में चलने की क्षमता हो। छाबा ने कहा, "पहले हमने कहा था कि कार का आकार चार मीटर से कम होगा। हमने कहा था कि 1.2 लीटर इंजन, 1.5 लीटर इंजन होगा और उसके आधार पर हमारे पास जीएसटी संरचना व्यापक थी। मुझे लगता है कि अब यह बीते दिन की बात हो गई है।"

वर्तमान में चार मीटर तक लंबे और 1200 सीसी पेट्रोल इंजन वाले हाइब्रिड पीवी या चार मीटर तक लंबे तथा 1,500 सीसी डीजल इंजन वाले हाइब्रिड यात्री वाहन (पीवी) पर बिना किसी उपकर के 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है। वहीं चार मीटर से अधिक या 1,200 सीसी पेट्रोल इंजन वाले हाइब्रिड पीवी या 1,500 सीसी डीजल इंजन वाले हाइब्रिड पीवी पर 15 प्रतिशत उपकर के साथ 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है। छाबा ने पूछा, "क्या हम संपूर्ण नीति निर्माण में क्रांति ला सकते हैं? क्या हम देश और उपभोक्ता के लिए जो महत्वपूर्ण है, उससे शुरुआत कर सकते हैं?"

उन्होंने कहा, "जीएसटी दरें देश के लिए महत्वपूर्ण चीजों पर आधारित होनी चाहिए जैसे कार की पर्यावरण अनुकूलता, आयात बिल को बचाने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की क्षमता, स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखला के साथ स्थानीयकरण तथा स्वामित्व की कम कुल लागत।" उन्होंने कहा, "तभी आप नीति बनाते हैं। उस नीति के आधार पर, यदि इलेक्ट्रिक वाहन सर्वश्रेष्ठ है, तो उसपर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।" उन्होंने कहा कि यदि सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) अच्छी है, तो उसे पेट्रोल तथा डीजल पर कुछ वरीयता दी जाएगी। छाबा ने सुझाव दिया, "पेट्रोल की तुलना में मजबूत हाइब्रिड को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी और ईवी सर्वोत्तम होगा।"

भारत ने 3 लाख करोड़ का माल बेचा और 56 अरब डॉलर का सामान खरीदा

कितना रहा जून में व्यापार घाटा

नई दिल्ली। एजेंसी

व्यापार के मोर्चे पर भारत लगातार तेजी हासिल कर रहा है, लेकिन आज भी आयात का बोझ कम नहीं हुआ। जून के आंकड़े देखें तो देश के निर्यात में बढ़ोतरी दिख रही, जबकि आयात भी बढ़ रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो देश का व्यापार घाटा भी कम नहीं हो रहा है. जून में भी देश का व्यापार घाटा करीब 21 अरब डॉलर रहा है। व्यापार घाटे का मतलब होता है कि देश में निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो रहा है। यानी देश अपना सामान बेच कम और दूसरे का खरीद ज्यादा रहा है। इसी के अंतर को व्यापार घाटा कहा जाता है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सोमवार को बताया कि देश में वस्तुओं का निर्यात जून में 2.56 प्रतिशत बढ़कर 35.2 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया. एक साल पहले इसी महीने में निर्यात 34.32 अरब डॉलर रहा था।

जून में कितना रहा आयात

आंकड़ों के अनुसार, जून में आयात लगभग 5 फीसदी बढ़कर 56.18 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान महीने 53.51 अरब डॉलर था। इस तरह देखा जाए तो निर्यात के मुकाबले आयात में दोगुनी वृद्धि दिख रही। यही देश के व्यापार घाटे को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है. जून में देश का व्यापार घाटा (आयात और निर्यात का अंतर) 20.98 अरब डॉलर रहा है।

800 अरब डॉलर जाएगा निर्यात

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल कहा कहना है कि मौजूदा रुख को देखते हुए देश का वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात चालू वित्तवर्ष में 800 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है. इस लिहाज से 800 अरब डॉलर का आंकड़ा पार होना मुश्किल नहीं है।

मई में ज्यादा था निर्यात

मई में भारत का वस्तुओं का निर्यात 9.1 प्रतिशत बढ़कर 38.13 अरब डॉलर रहा था, जबकि व्यापार घाटा बढ़कर सात महीने के उच्चतम स्तर 23.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून के दौरान निर्यात 5.84 प्रतिशत बढ़कर 109.96 अरब डॉलर और आयात 7.6 प्रतिशत बढ़कर 172.23 अरब डॉलर रहा है. इस तरह पहली तिमाही में व्यापार घाटा करीब 62 अरब डॉलर रहा है।

दालों की कीमतों में गिरावट, खुदरा बाजार में क्यों नहीं मिली राहत, सरकार ने रिटेलर्स को दी चेतावनी

नई दिल्ली। एजेंसी

यह पिछले दिनों की ही बात है। सरकार ने बताया था कि दालें, खास कर अरहर या तुअर और उड़द की दाल की थोक कीमतें घटी हैं। सरकार ने बताया था कि इन दालों की कीमतों में करीब चार फीसदी की कमी हुई है। इसके साथ ही उम्मीद जताई गई थी कि अब खुदरा बाजार में भी कीमतें कम होंगी। लेकिन, रिटेल बाजार में इन दालों की कीमत घटने के बजाय बढ़ गईं। इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश के टॉप रिटेलरों के साथ बैठक की है। सरकार ने इन्हें एक तरह से चेतावनी दी है कि थोक बाजार के अनुरूप ही खुदरा बाजार में भी कीमतें कम हो।

क्या हुआ है डेवलपमेंट

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बीते दिन रिलायंस रिटेल, डी मार्ट, टाटा स्टोर्स, स्पेंसर्स, आरएसपीजी, वी मार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने रिटेलर्स को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दालों की कीमतें कम नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई होगी।

क्यों देनी पड़ी चेतावनी

पिछले कुछ दिनों से थोक मंडियों में तुअर, चना और उड़द जैसी प्रमुख दालों की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। लेकिन, रिटेल बाजार में यह कमी नहीं दिख रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4इ तक की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा कीमतों में समान गिरावट नहीं देखी गई है।

होगी सख्त कार्रवाई

रिटेलर्स के साथ बैठक में निधि खरे ने कहा कि अगर स्टॉक सीमा का उल्लंघन, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि अब सरकार की इन कमोडिटी पर कड़ी नजर रहेगी। साथ ही जमाखोरी के नियमों का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा।

खरीफ में दलहन की हो रही अच्छी बुवाई

उपभोक्ता मामले के सचिव ने यह भी बताया कि खरीफ दलहन की बुवाई अच्छी रही है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दलहन का रकबा बढ़कर 62.32 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल यह 49.50 लाख हेक्टेयर था। दलहन में तुअर की खेती 9.66 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.14 लाख हेक्टेयर हो गई है। खरे ने रिटेल उद्योग से दालों की कीमतों को उपभोक्ताओं के लिए किफायती रखने के सरकार के प्रयासों में हर संभव मदद करने को कहा।

गुरू पूर्णिमा पर इन राशियों को मिलेगी सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कृपा

गुरु पूर्णिमा का पर्व साल 2024 में 21 जुलाई, रविवार के दिन मनाया जाएगा. आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. इस दिन हिंदू महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था. इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं. गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का पूजन किया जाता है. शिष्य अपने गुरु की आराधना करते हैं. गुरु, अर्थात वह महापुरुष, जो आध्यात्मिक ज्ञान एवं शिक्षा द्वारा अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं.

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

गुरु पूर्णिमा 2024 तिथि

आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई, शनिवार के दिन शाम 5.59 मिनट पर लग जाएगी. इस तिथि का समापन 21 जुलाई, रविवार को दोपहर 3.46 मिनट पर होगा. इसी कारण पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई, 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा. साथ ही गुरू पूर्णिमा का पर्व देव गुरु को समर्पित होता है. गुरु पूर्णिमा पर इन राशियों को मिलेगी सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कृपा. जानें कौन-सी हैं वो लकी राशियां.

धनु राशि - धनु राशि वालों को साल 2024 में गुरु पूर्णिमा के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो सकती है. धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति जो ज्ञान, शिक्षा के कारक हैं. धनु राशि वालों पर 21 जुलाई के दिन गुरु देव बृहस्पति का आशीर्वाद बना रहेगा. अगर आप शिक्षा से जुड़ा कोई काम शुरु करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत शुभ है.

मीन राशि - मीन राशि वालों को भी गुरु पूर्णिमा के दिन देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा. इमीन राशि के स्वामी हैं गुरु देव बृहस्पति जो ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं. इस दिन अगर आपके बच्चे की राशि मीन है तो आप उसकी शिक्षा की शुरुआत से दिन से करा सकते हैं और इस दिन बच्चे में गुरुओं और पुजारी से आशीर्वाद दिलवाएं. इस दिन किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, आद का दिन आपके लिए अति शुभ रहेगा.

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

21 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा, करें इन विशेष चीजों का दान

हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व हैं। गुरू पूर्णिमा आषाढ़ माह के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती हैं।

गुरु, जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक हैं। गुरु व्यक्ति को अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाते हैं। गुरु जातक को सही मार्ग दिखाते हैं। इस दिन को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता हैं। इस दिन इन विशेष चीजों का दान करना शुभ माना जाता हैं।

करें केसर का दान

गुरु पूर्णिमा के दिन केसर का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता हैं। ऐसा माना जाता है कि केसर का दान करने से ज्ञान, बुद्धि, विद्या और सफलता प्राप्त होती हैं। केसर का दान करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती हैं।

करें पीले वस्त्र का दान

पीला रंग गुरु ग्रह का प्रिय रंग माना जाता हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती हैं।

करें चने का दान

चने का दान गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक विशेष दान हैं। चने का दान करने से गुरु की कृपा बनी रहती हैं।

सावन में कांवड़ यात्रा का हैं विशेष महत्व, जानें इससे जुड़ी पौराणिक कथा

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
9826384585

हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया हैं। इस वर्ष सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई, सोमवार से होगी। इसी दौरान कावड़ यात्रा की भी शुरूआत होती हैं। कांवड़ यात्रा में कांवड़िया गंगा नदी में स्नान कर लोटे में जल भरकर शिव मंदिर में सावन शिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं। मान्यता है की कांवड़ यात्रा को लेकर आने से भगवान शिव कांवड़िया की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता हैं। इस दौरान कांवड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को कई सख्त नियमों का पालन करना पड़ता हैं। इस दौरान भक्तों को पैदल ही पूरी यात्रा करनी पड़ती हैं। साथ ही यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन करना होता हैं। इसके अलावा, आराम करते समय कांवड़ को जमीन पर रखना वर्जित होता है, बल्कि कांवड़ को किसी पेड़ पर लटकाया जाता हैं। कांवड़ को जमीन पर रखने से वह अपवित्र हो जाता हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त नंगे पांव चलते हैं और स्नान करने के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता हैं।

पौराणिक मान्यता

पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले भगवान शिव विष पीकर पूरी दुनिया की रक्षा की थी। विषपान करने से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता हैं। ऐसा कहते हैं इसी विष के प्रकोप को कम कर उसके प्रभाव को ठंडा करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता हैं।

आखिर क्यों सावन में हरे रंग को माना जाता हैं शुभ, जानिए महत्व

पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष
आचार्य वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

सावन का महीना सुहागिन औरतों के लिए त्योहारों बौछार लाता हैं। भगवान शिव का प्रिय होने से इस माह को बेहद पवित्र माना जाता हैं। इस माह से हिंदू त्योहारों की शुरुआत हो जाती हैं। इस साल यह 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त तक रहेगा। यह महीना व्रत और पूजा-पाठ के लिए खास होता है।

इसी प्रकार सावन में हरे रंग का विशेष महत्त्व माना गया हैं। सावन में औरतें नाचती गाती पुरे माह को मस्ती से बिताती हैं। सावन में महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां भी पहनती हैं, लेकिन क्या है इसके पीछे का कारण जानिए आखिर क्यों महिलाएं हरे रंग महत्त्व देती हैं।

सावन में हरे रंग को क्यों शुभ माना हैं?

सावन के महीने में महिलाएं हरी चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। यहां तक कि महिलाओं द्वारा लगाई जाने वाली मेहंदी भी हरे रंग की ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सावन के दौरान हरे रंग को शुभता प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में हरे रंग का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व है। इस रंग का संबंध विवाह और शुभता से है। कहते हैं किसावन के दौरान हरी चूड़ियां और वस्त्र पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति और भगवान शिव से आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता हैं की भगवान शिव को भी हरा रंग बेहद प्रिय है यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का खास महत्व होता है।

सावन का महीना त्योहारों, व्रत, पूजा पाठ हर तरिके से बेहद खास होता है, यह माह प्रेम के प्रतीक माना जाता है। सावन में शिव पूजन से अखंड सौभग्यवती का आशिर्वाद प्राप्त होता है। सावन में व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करने से मां पार्वती और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही, सुहागिनों को सुखी वैवाहिक जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है। इस माह हिंदू धर्म से सभी त्योहारों से शुरुआत होती हैं।

बेलपत्र के अलावा ये 8 पत्ते भी भगवान शिव को हैं अतिप्रिय

पूजा में जरूर करें उपयोग

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषाचार्य एवं
रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत होने जा रही है। इस माह भगवान शिव का पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी शुभ माना गया है। यह माह भोलेनाथ को अति प्रिय है। सावन सोमवार पर भगवान शिव के निमित्त व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आप पूजा के दौरान कुछ पत्तों को भी पूजन सामग्री में शामिल करते हैं, तो इसके आपको शुभ फल मिलेंगे।

1. आंकड़े

हिंदू मान्यता के अनुसार, आंकड़े के फूल के साथ भगवान शिव को इसके पत्ते भी अति प्रिय है। आप पूजा के दौरान आंकड़े के पत्ते महादेव को 7, 9, 11 अथवा 21 के क्रम में चढ़ा सकते हैं।

2. पीपल

हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व है। आप सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव को बेलपत्र के स्थान पर पीपल के पत्ते भी अर्पित कर पूजा सकते हैं।

3. शमी

शिव महापुराण में शमी के पेड़ का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार, आप पूजा के दौरान भगवान शिव को शमी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं।

4. धतूरा

भगवान शिव को धतूरे के फल के साथ इसके पत्ते भी चढ़ाए जा सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव को धतूरे के पत्ते प्रिय है। ऐसे में धतूरा न उपलब्ध होने पर आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं।

5. भांग

भगवान शिव को पूजा के दौरान भांग अर्पित की जाती है। इसके साथ ही आप शिवलिंग पर भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं।

6. दूर्वा

भगवान शिव को आप दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में दूर्वा को अमृत के समान माना गया है। इससे साधक की आयु लंबी होती है।

7. अपामार्ग

सोमवार को पूजा के दौरान आप भगवान शिव पर अपामार्ग के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

8. बांस

भोलेनाथ को बांस के पत्ते चढ़ाना भी शुभ माना गया है। मान्यता के अनुसार इससे साधक को संतान प्राप्ति होती है।

थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एनवीडिया ने एमओयू साईन करने की घोषणा की

एआई -सक्षम विश्वविद्यालय स्थापित कर भारत में उच्च शिक्षा को नया आयाम देगें

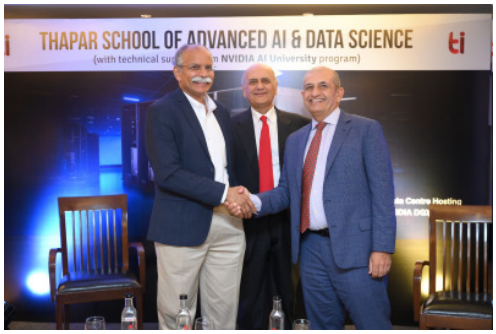

दिल्ली एनसीआर। आईपीटी नेटवर्क

थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (टीआईइटी) ने एनवीडिया (एनवीडिया) के साथ एक एमओयू साईन करने की घोषणा की, जिसके तहत एनवीडिया (एनवीडिया) एआई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के तकनीकी सहयोग से थापर स्कूल ऑफ एडवांस्ड एआई एंड डेटा साइंस (टीएसएएआई) की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दुनिया भर के उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, शिक्षा के भविष्य को नया रूप दे रही है और जीवन को बदल रही है। टीआईइटी और एनवीडिया के बीच एमओयू के तहत, थापर स्कूल ऑफ एडवांस्ड एआई एंड डेटा साइंस की स्थापना टीआईइटी के पटियाला कैंपस में की जाएगी। इस इनोवेटिव इनिशिएटिव का उद्देश्य छात्रों और संकाय दोनों को एआई कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए कॉम्प्रेहेंसिव एकेडमिक प्रोग्राम, रिसर्च ओपोर्चुनिटी और इनोवेशन प्रोजेक्ट प्रदान करना है।

थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉ. पद्मकुमार नायर ने कहा, 'हम एनवीडिया के तकनीकी सहयोग से इस एआई स्कूल की स्थापना करने के अवसर को लेकर उत्साहित हैं। यह कार्य न केवल एआई विशेषज्ञता में अंतर को पाटेगा बल्कि इस परिवर्तनकारी क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह हमारे दृष्टिकोण को और भी सुदृढ करता है जो भविष्य के लिए तैयार छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का है।' एनवीडिया के एशिया साउथ के प्रबंध निदेशक विशाल धूपर ने कहा, 'ग्लोबल एआई एजुकेशन इनिशिएटिव में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, थापर इंस्टीट्यूट पूरे भारत में एआई विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए अत्याधुनिक एनवीडिया तकनीकों को एक साथ लेकर आएगा। नया एआई स्कूल एआई विशेषज्ञता में अंतर को पाटने में मदद करेगा और उद्योग में शानदार रिसर्च और इनोवेशन का रास्ता मजबूत करेगा।'

टीआईइटी जेनरेटिव एआईके विकास और तैनाती के लिए एनवीडिया ङ्खें सिस्टम, एनवीडिया प100 टेंसर कोर जीपीयू, एनवीडिया "100 टेंसर कोर जीपीयू और एनवीडिया एआईएंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए अत्याधुनिक एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगा। यह समर्पित डेटा केंद्र लगभग 8 टेराबाइट जीपीयू मेमोरी के साथ 227 पेटाफ्लॉप्स एआईप्रदर्शन प्रदान करेगा।

फलों और सब्जियों की पैकिंग के बिजनेस से करें मोटी कमाई, 75% मिलती है सब्सिडी

एजेंसी

आज कल के इस अर्थयुग में कई तरह के बिजनेस शुरू हुए हैं। जिनसे घर बैठए भी बंपर कमाई की जा सकती है। किसानों के लिए भी इसमें कई मौके सामने आ रहे हैं। वैसे भी देश के किसान अब खेती तक ही सीमित नहीं है। वो शुपालन, मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग जैसे दूसरे कृषि से जुड़े बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं। इन दिनों मौसम भी काफी बेमौसम हो जाता है। ऐसे में किसानों को अपनी उपज संभालना काफी बड़ा काम है। इसी कड़ी में आप फलों और सब्जियों को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए पैक हाउस (ईम्ि प्दले) की स्थापना कर सकते हैं।

पैक हाउस बनाने के लिए बिहार सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसमें 50 फीसदी से लेकर 75 फीसदी तक सब्सिडी शामिल है। फल और सब्जियों की उपज को विदेशों में निर्यात करने के लिए पैक हाउस की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। पैक हाउस बिजनेस के लिए मिलती है सब्सिडी

बिहार सरकार सब्जियों और फलों की सही ढंग से पैकिंग के लिए पैक हाउस की स्थापना करने पर जोर दे रही है। इसमें किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। इन पैकिंग हाउस की लागत करीब 4 लाख रुपये है। इसमें 50 फीसदी सब्सिडी मिलने पर किसानों को कुल 2 लाख रुपये बतौर ग्रांट आसानी से मिल जाएगें। इसके अलावा इझ्ध/इझ्ण से जुड़े किसान समूहों को कुल 75 फीसदी यानी 3 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पैक हाउस बनाने के लिए यह सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।

पैक हाउस के लिए ऐसे करें अप्लाई बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की ओर से पैक हाउस पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिले के सहायक निदेशक, उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं। पैक हाउस बनाने के लिए अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। पैक हाउस यूनिट लगाने के बाद कृषि विभाग की जांच कमेटी की ओर निरीक्षण किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी किसान को सब्सिडी की रकम मुहैया करवाई जाती है। वहीं बिहार सरकार पैक हाउस के अलावा कोल्ड स्टोरेज पर भी किसानों को बंपर सब्सिडी दे रही है।

भारी बारिश के बाद सब्जियों ने दिखाए तेवर, महंगाई से टमाटर 'लाल'

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का असर अब सब्जियों पर दिखने लगा है। इंदौर में भारी बारिश के बाद टमाटर का भाव बढ़ गया है। अब यह 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बारिश से टमाटर की फसल खराब होने और आवक कम होने के कारण दाम बढ़े हैं। सितंबर-अक्टूबर में मालवा-निमाड़ के टमाटर मंडी में आने के बाद भाव कम हो सकते हैं। अभी इंदौर में टमाटर महाराष्ट्र और बेंगलुरु से आ रहा है। भारत में टमाटर की प्रति हेक्टेयर उपज कम होने से भी भाव बढ़ रहे हैं।

इंदौर में मंगलवार को थोक टमाटर के भाव 70-72 रुपए प्रति किलोग्राम थे। लेकिन आवक कम और मोहर्रम की छुट्टी के चलते मांग बढ़ने से भाव 100-115 रुपए किलो तक पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र में बारिश से फसल खराब होने के कारण टमाटर की सप्लाई कम हो गई है। अभी इंदौर में टमाटर महाराष्ट्र के संगमनेर और नारायण गांव के अलावा बेंगलुरु से आ रहा है। सितंबर-अक्टूबर में मालवा-निमाड़ और मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों से टमाटर की आवक शुरू होने के बाद भाव कम होने की उम्मीद है। तब इंदौर से टमाटर का निर्यात भी शुरू हो जाएगा।

अन्य सब्जियों के रेट

बता दें कि चोइथराम मंडी में सरजना फली 80-100 रुपए किलो, हरी मिरची 55-60 रुपए किलो, हरी धनिया 60 रुपए किलो, बैगन 15-20 रुपए किलो, ककड़ी 25-30 रुपए किलो, कद्दू 20 रुपए किलो, पत्ता गोभी 25-30 रुपए किलो, फूल गोभी 30-35 रुपए किलो, लौकी 20-25 रुपए किलो, गिलकी 25-30 रुपए किलो, भिंडी 30-40 रुपए किलो, ग्वार फली 50-60 रुपए किलो, बालौर 50-60 रुपए किलो, पालक 20-30 रुपए किलो और रामकली कैरी 50-60 रुपए किलो बिक रही है।

प्रति हेक्टेयर उपज कम

वर्तमान में, भारत दुनिया में टमाटर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन, प्रति हेक्टेयर उपज कम होने के कारण भाव ज्यादा रहते हैं। पहले नंबर पर चीन है। देश में टमाटर की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में होती है।

Jio, Airtel, Vi बायकॉट का कितना असर? बढ़े मोबाइल रिचार्ज के बाद की पहली TRAI रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की तीन सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने हाल ही में मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर व्द, Airtel और Vi के बायकॉट की मुहिम चल रही है। हालांकि यह मुहिम सोशल मीडिया तक दिख रही है, क्योंकि इन तीनों टेलिकॉम ऑपरेट के मुकाबले में सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL मौजूद है, जिसकी हालात से सभी वाकिफ है। BSNL के पास 4G कनेक्टिविटी है, जो देशभर में मौजूद नहीं है। साथ ही नेटवर्क क्वॉलिटी एक अलग मुद्दा है। इस बीच सरकारी संस्था टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने खुद मंथली रिपोर्ट जारी करके हालात बयां कर दिए हैं। यह ट्राई की मई 2024 की रिपोर्ट हैं, जिस वक्त तक भारत में मोबाइल रिचार्ज की कीमत नहीं बढ़ी थी।

जियो बनी मार्केट लीडर

अगर ट्राई की मई 2024 की रिपोर्ट पर गौर करें, तो मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो मार्केट लीडर बनी हुई है, जिसको सबसे ज्यादा मुकाबला भारती एयरटेल से मिल रहा है, जबकि वोडाफोन-आइडिया हर बार के अपने परफॉर्मेंस को दोहराते हुए लगातार ग्राहकों से दूर होती जा रही है। मतलब वोडाफोन-आइडिया साफतौर पर मैदान छोड़ चुकी है।

जियो और एयरटेल सबसे आगे

अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें, तो मई में जियो ने करीब 22 लाख नए ग्राहक जोड़ लिए है। यही वही ग्राहक हैं, जो BSNL और VI सर्विस छोड़कर आ रहे हैं। इसमें माह दर माह 0.46 फीसद की ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि जियो के मुकाबले वाली एयरटेल ने मई माह में अपने साथ 12.5 लाख नए ग्राहक जोड़ लिए हैं। इस तरह एयरटेल के ग्राहक जोड़ने की दर में माह दर माह के हिसाब से 0.32 फीसद का ग्रोथ दर्ज की गई है।

Vi आंकडों में सबसे पीछे

वही वोडाफोन-आइडिया इस आंकड़ों के खेल में पिछड़ रही है। कंपनी ने मई 2024 में 9,24,797 ग्राहक खो दिए हैं, जो न्न का पिछले तीन माह का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। इस दौरान मंथली हिसाब से 0.42 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।

क्या है एक्टिव यूजर्स

अगर एक्टिव यूजर्स की बात करें, तो इस मामले में एयरटेल सबसे ज्यादा है एयरटेल के पास 99.4 फीसद एक्टिव यूजर्स हैं। बात एक्टिव यूजर्स की करें, तो वो यूजर्स जो सिम कार्ड इश्यू कराने के बाद उस पर लगातार रिचार्ज कराते हैं, उन्हें एक्टिव यूजर्स कहा जाता है। मई में एयरटेल के एक्टिव यूजर बेस 38.7 करोड़ हो गया है, जो अप्रैल में 38.6 करोड़ था। वही जियो का एक्टिव यूजर 47.4 करोड़ हो गया है, जो एक माह पहले 47.2 करोड़ था। Vi का एक्टिव यूजरबेस 21.9 करोड़ हो गया है, जो 21.8 करोड़ हुआ करता था।

जियो की बादशाहत बरकरार

अगर वायरलेस कैटेगरी की बात करें, तो जियो का मार्केट शेयर 40.60 फीसद है। साथ ही जियो का सब्सक्राइबर बेस 47.4 करोड़ है। वही एयरटेल का मार्केट शेयर 33.17 फीसद है और यूजरबेस 38.7 करोड़ है, जबकि Vi का मार्केट शेयर 18.6 फीसद है, जबकि यूजरबेस 21.8 करोड़ है। वायरलाइन और वायरेल कैटेगरी में जियो सबसे ज्यादा यूजर के साथ पहले पायदान पर है। वही लैंडलाइन सेगमेंट में भी जियो की बादशाहत बरकरार है। जियो ने तीन गुना सब्सक्राइबर्स अपने साथ जोड़े हैं।

Canon ने EOS R1 और EOS R5 मार्क-II पेश किए

फिल्ममेकिंग और फोटोग्राफी में अगली जनरेशन का इनोवेशन शुरू

इंदौर। एजेंसी

डिजिटल इमेजिंग सॉल्यूशंस में अग्रणी कंपनी, Canon इंडिया ने अपनी EOS R सीरीज़ में दो बेहतरीन उत्पादों EOS R1 और EOS R5 मार्क II का अनावरण किया। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेगमेंट की लीडर, Canon इन उत्पादों के नेक्स्ट-जेन फीचर्स, क्वालिटी, स्पीड और सुविधा द्वारा एक बार फिर उद्योग में क्रांति लाने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने के लिए तैयार है।

EOS R1 कंपनी का पहला फ्लैगशिप EOS R सिस्टम कैमरा है। यह मीडिया एवं वीडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक्शन जॉनर के फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें शूटिंग की गंभीर स्थितियों में भी महत्वपूर्ण क्षणों को कैप्चर करना होता है। अपने शक्तिशाली नए इमेज प्रोसेसिंग और ऑटोफोकस सिस्टम के साथ, यह नया कैमरा डिजिटल युग में सबसे तेज स्पीड के साथ नए मानक स्थापित कर रहा है।

EOS R5 मार्क II एक फुल-फ्रेम मिररलेस कैमरा है जो EOS R5 से ज्यादा आधुनिक है। इसमें हाई-परफॉरमेंस नए 45-मेगापिक्सल बैक-इलुमिनेटेड (BI) स्टैक्ड सीमॉस सेंसर और एक्सेलेरेटेड कैप्चर इमेज प्रोसेसर सिस्टम के साथ अत्याधुनिक विशेषताएं हैं। साथ ही, आई कंट्रोल एएफ और सिनेमा EOS फीचर्स के साथ यह कैमरा Canon के EOS सिस्टम में प्रतिष्ठित '5 सीरीज़' को नेक्स्ट जनरेशन में ले गया है। इन फ़ंक्शनलिटीज़ के कारण EOS R5 मार्क II को फ़ोटो और मूवी प्रोफ़ेशनल्स के लिए एक ऑल-राउंडर कैमरा है।

इस लॉन्च के बारे में ष्टंहदह इंक. के एक्ज़िक्यूटिव ऑफिसर, Canon मार्केटिंग एशिया के प्रेसिडेंट एवं सीओओ और Canon सिंगापुर के प्रेसिडेंट एवं सीईओ, श्री टाइगर इशी ने कहा, 'तकनीकी प्रगति और रचनात्मक इनोवेशन के जीवंत केंद्र के रूप में, भारत Canon की वैश्विक विकास की रणनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ हमारा कैमरा व्यवसाय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसने डीआईएलसी सेगमेंट में हमें बाज़ार में अग्रणी बाजार अंश दिलाया है। हम EOS सीरीज़ की अपनी विरासत मजबूत कर रहे हैं और EOS R1 एवं EOS R5 मार्क II का लॉन्च यूज़र्स को समर्थ बनाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

व्हाट्सऐप ने यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिये ग्रुप मैसेजिंग में कंटेक्स्ट कार्ड की पेशकश की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

व्हाट्सऐप एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिससे यूजर्स को ग्रुप मैसेजिंग में सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति ने एक ग्रुप में जोड़ा है, तो अब आपको उस ग्रुप के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला एक कंटेक्स्ट कार्ड नजर आएगा। इस कार्ड से आपको पता चलेगा कि आपको ग्रुप में किसने जोड़ा, वह ग्रुप कब बना और उसे किसने बनाया। फिर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको ग्रुप में रहना है या नहीं। आप व्हाट्सऐप पर सुरक्षित रहने के लिये उपलब्ध कुछ सेफ्टी टूल्स को रिव्यू भी कर सकते हैं। यह खासकर तब मदद करता है, जब आप किसी व्यक्ति या लोगों के एक समूह से हाल ही में जुड़े हों, लेकिन आपने उन्हें अपने कॉन्टैक्ट में सेव नहीं किया है। या इससे पुष्टि होती है कि आप उस ग्रुप को जानते हैं या नहीं अथवा उसमें रहना चाहते हैं या नहीं। यह अपडेट व्हाट्सऐप यूजर्स को सुरक्षा की एक और परत प्रदान करता है। इसे मौजूदा फीचर्स, जैसे कि अनजाने कॉलर्स को म्यूट करना, चैट लॉक, इन-ऐप प्राइवेसी चेक-अप और यह तय करना कि कौन आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकता है के आधार पर बनाया गया है। यह 1:1 मैसेजिंग के मौजूदा अनुभव के समान है, जिसमें यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको मैसेज करता है तो आपको ज्यादा कंटेक्स्ट दिए जाते हैं ।

टाटा मोटर्स के यात्री वाहनों की बिक्री ग्रामीण बाजार में 5 साल में 4 गुना बढ़ी

वित्त वर्ष 2024 में टाटा के यात्री वाहनों की बिक्री में ग्रामीण बाजार ने 40% का योगदान किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी, टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण इलाकों में जोरदार बिक्री की है। ग्रामीण इलाकों की बिक्री ने कंपनी के कुल यात्री वाहनों की बिक्री में 40 फीसदी का योगदान दिया है। टाटा मोटर्स की कारों और एसयूवी की नई फॉरएवर रेंज की लोकप्रियता ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच काफी बढ़ी है। इस रेंज में पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या 70 फीसदी है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल पहुंच में विस्तार और खरीदारी की बढ़ती शक्ति के साथ ग्रामीण और शहरी ग्राहकों के बीच का अंतर कम हो रहा है। टाटा मोटर्स की कारों और एसयूवी की नई फॉरएवर रेंज ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। यह रेंज भविष्य की डिजाइन, शानदार प्रदर्शन और उन्नत तकनीक और सेफ्टी फीचर्स की एक सीरीज के साथ आती है। ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स की सफलता इसके खास तरह के वाहनों और ग्रामीण उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों की गहरी समझ से प्रेरित है। ग्रामीण बाजारों की व्यापक क्षमता और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का फायदा उठाकर टाटा मोटर्स अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। साथ ही बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहती है।

OPPO इंडिया ने Reno12 5G सीरीज़ लॉन्च की

एआई फोन की उपलब्धता आसान बनाई

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

OPPO इंडिया ने रेनो 12 सीरीज़ लॉन्च की। यह देश में एआई फोन की उपलब्धता बढ़ाने की ओर कंपनी का पहला कदम है। रेनो 12 सीरीज़ "आपकी दैनिक सहयोगी" है। इसमें एआई इरेज़र 2.0, एआई क्लियर फेस, और स्मार्ट इमेज मैटिंग 2.0 जैसी खूबियाँ हैं, जो बिना किसी जटिल इमेज एडिटिंग के बेहतरीन और मनोरंजक फोटो प्रदान करती हैं। इस डिवाईस में एआई टूलबॉक्स दिया गया है, जो गूगल जेमिनी एलएलएम द्वारा पॉवर्ड है। इसमें टूलबॉक्स में एआई राईटर, एआई समरी, एआई स्पीक आदि हैं, जिनसे दैनिक उत्पादकता बढ़ती है।

Reno12 Pro 5G दो वैरिएंट में उपलब्ध होगा। इसका 12जीबी+256जीबी का वैरिएंट 36,999 रु. में और 12जीबी+512जीबी का वैरिएंट 40,999रु. में मिलेगा। रेनो12 5जी का मूल्य 32,999रु. होगा और यह 8जीबी रैम एवं 256जीबी स्टोरेज के वैरिएंट में आएगा। Reno12 Pro 5G की सेल भारत में 18 जुलाई को शुरू होगी और Reno12 5G 25 जुलाई से OPPO e-Store, Flipkart, और सभी मेनलाईन रिटेल आउटलेट्स पर मिलना शुरू होगा।

इस लॉन्च के बारे में पीटर डोह्युंग ली, हेड ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेट्जी, OPPO ने कहा, "रेनो 12 सीरीज़ OPPO की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ हमने एआई फोन को अपनाने में तेजी लाई है। रेनो सीरीज़ में ध्झ्ध्र की आधुनिक जेनएआई क्षमताएं, फ्यूचारिस्टिक फ्लुड डिज़ाईन, और अतुलनीय एनर्जी एफिशियंसी दी गई हैं, जिनसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

स्टाईलिश और ड्यूरेबल डिज़ाईन

रेनो12 प्रो में 43-डिग्री कर्व के साथ अद्वितीय क्वाड-माईक्रो कर्व्ड इन्फाईनाईट व्यू स्क्रीन है, इसलिए इसके बेज़ेल्स बहुत पतले यानी केवल 1.69मिमी के हैं, और स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात केवल 93.5 प्रतिशत है। इन दोनों डिवाईस में स्मूथ ब्राउज़िंग और स्क्रॉलिंग के लिए 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच का एफएचडीइ एमोलेड डिस्प्ले लगा है। 1200 निट्स की पीक ब्राईटनेस के साथ तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन साफ दिखाई देती है।

इस हैंडसेट में 10-बिट पैनल हैं, जो 1.07 बिलियन कलर्स का आउटपुट प्रदान करते हैं ताकि उच्च डायनामिक रेंज (एचडीआर) की इमेज प्राप्त हों। जीवंत एवं सुंदर पिक्चर्स के लिए सूक्ष्म कलर ग्रेडेशन भी इसमें दिया गया है।

सही डील मिले तो 75 प्रतिशत भारतीय ज्यादा ट्रिप करने के लिए तैयार- अध्ययन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

ग्लोबल ट्रैवल मार्केटप्लेस स्काईस्कैनर के नए अध्ययन में सामने आया है कि भारतीयों को घूमना बहुत पसंद है। वो सस्ते विकल्प चाहते हैं और हमेशा बेहतरीन डील की तलाश में रहते हैं। इन यात्रापसंद लोगों को गर्मियों में भारी बचत करने में मदद करने के लिए स्काईस्कैनर ने एकोमोडेशन के लिए 'लाउड बजटिंग गाईड' पेश की है। विश्व में लाखों एकोमोडेशन मूल्यों के विश्लेषण के बाद निर्मित यह गाईड यात्रियों को सबसे अच्छी डील तलाशने में मदद करती है।

मोहित जोशी, ट्रैवल एवं डेस्टिनेशन एक्सपर्ट, स्काईस्कैनर ने कहा बेहतरीन फ्लाईट डील का रोमांच हम सभी जानते हैं, लेकिन होटल भी बचत का खजाना पेश कर सकते हैं। केवल सबसे सस्ते विकल्प तलाशने की बजाय विभिन्न तरह के एकोडोमेशन, जैसे अपार्टमेंट या सेल्फ-केटरिंग स्टे भी तलाशकर देखें। हो सकता है कि आपको अपनी ट्रिप के अनुरूप ज्यादा आरामदायक और बजट-फ्रेंडली जगह मिल जाएं।

वनपोल के साथ गठबंधन में किए गए स्काईस्कैनर के नए अध्ययन के आँकड़ों में सामने आया है कि 84 प्रतिशत भारतीय यात्री गर्मी की छुट्टियों के लिए एकोमोडेशन पहले ही बुक कर चुके हैं, लेकिन उनकी और ज्यादा घूमने की उत्सुकता अभी भी शेष है। उनकी इसी इच्छा के कारण अतिरिक्त ट्रिप्स की संभावनाएं बनती हैं, और इनमें से 75 प्रतिशत यात्रियों ने संकेत दिया है कि यदि उन्हें बहुत आकर्षक डील मिलेगी, तो वे एक बार और छुट्टियों पर जा सकते हैं। जहाँ यात्रा का बजट महत्वपूर्ण है, वहीं अच्छी डील का मिलना आवश्यक है।

होटल ब्रेक के लिए 3@5 सबसे सस्ते समर स्पॉट्स देखें रू स्काईस्कैनर के डेटा एक्सपट् स ने आँकड़ों का विश्लेषण कर इन गर्मियों में सबसे सस्ते स्थान पेश किए हैं। क्या आप 4-स्टार की बेहतरीन डील चाहते हैं? तो भारत में मनाली या तिरुवनंतपुरम आईये और केवल 3064 रुपये प्रति रात्रि के औसत मूल्य में 4-स्टार होटल का आनंद लीजिए। क्या आपको लक्स-फॉर-लेस स्टे के और ज्यादा विकल्प चाहिए? तो इस अगस्त गुलमर्ग में केवल 4,966 रुपये प्रति रात्रि के औसत मूल्य में 5-स्टार होटल का आनंद लीजिए।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।